



न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म. ५. इटावा जिला
 प्रकरण नं० R/3618/18 कृषि विविध-6487/2018/इटावा/भू.

तुलसीराम पुत्र श्री शंकरप्रसाद कटार
 निवासी - कालहउ तहसील - विरमिया
 जिला - इटावा (म. ५.)

वगम - - - आवेदक

गजराजसिंह पुत्र श्री देवकरन सिंह राष्ट्रपुत्र
 निवासी - गडम - सिगाधउ तहसील - इटावा
 जिला - खण्डवा (म. ५.) हाल - निवासी
 गडम - कालहउ तहसील - विरमिया जिला - इटावा
 - - - मनावेदक

श्री सुब्रह्मण्य स्वामी
 आज दि. 17-12-18
 प्रस्तुत प्रारम्भिक तर्क हेतु
 दिनांक 20-12-18 4.01.19
 राजस्व मण्डल म. ५. इटावा

निगरानी को उग्रस्थिति करने हेतु धारा 32 म. ५ राजस्व की
 शर्तों के अन्तर्गत 151 सी.पी.सी.-1909 के अन्तर्गत कानून पर

माननीय महोदय

1. मद्रास निगरानी प्र. 30 R-3618/18 नि. में उक्त वेबसाइट 19.06.2018 को
 आवेदक एवं उसके अधिवक्ता श्री अनुपसिंह के कदम चैबी के निरस्त
 कर दिया गया, आवेदक के अधिवक्ता जिला न्यायालय में अनुरोध
 में प्राप्त होने से मामला परन्तु 2.35 P.M पर उपस्थित हुए
 तब वारंट हुआ कि प्रकरण कदम चैबी के निरस्त कर दिया है
2. मद्रास आवेदक दि. 18.06.18 से 16.12.2018 तक डेप्युटी मजिस्ट्रेट
 डाक से पीडित होने से उक्त प्रकरण के दि. 19.06.2018 को
 उपस्थित नहीं हो सका, परे कृपया कृपया न्यायालय में अनुरोध
 से वह भी कदम चैबी नहीं रखे /
3. मद्रास आवेदक के निगरानी होने से व उसके अधिवक्ता श्री अनुपसिंह
 का पता व ठिकाना तथा सहायक न्यायाधीश के निगरानी प्र. 30
 R-3618/18 नि. में जारी आदेश दि. 19.06.2018 को निरस्त कर उक्त
 निगरानी को उग्र. नम्बर पर लिगा. लाकर गुणदोषों पर निरन्तर करने
 कृपया करें।

दिनांक - 17.12.2018

(Signature)
 न्यायाधीश

(Signature)
 तुलसीराम पुत्र शंकर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. 6487 / 2018 / हरदा / भू0रा0

तुलसीराम

विरूद्ध

गजराजसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7-8-2019	<p>आवेदक अभिभाषक द्वारा रेस्टोरेशन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।</p> <p>2/ आवेदक की ओर से निगरानी प्रकरण 3618/2018/अपील/भू0रा0 में दिनांक 19-6-2018 को अदम पैरवी में खारिज होने के पश्चात यह रेस्टोरेशन आवेदन दिनांक 04-01-2019 को प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब से रेस्टोरेशन प्रस्तुत करने का कारण उनके द्वारा आवेदक के बीमार होना बताते हुये उसकी अनुपस्थिति को सद्भाविक मानते हुये अदम पैरवी में खारिज आदेश दिनांक 19-6-2018 को निरस्त कर मूल निगरानी को पुनः नम्बर पर लिये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>3/ मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत मेडिकल सर्टिफिकेट का अवलोकन किया। आश्चर्यजनक रूप से मेडीकल सर्टिफिकेट विशिष्ट रूप से उसी सम्पूर्ण अवधि का है जो कि मूल प्रकरण में अनुपस्थिति के दिनांक से लेकर वर्तमान रेस्टोरेशन आवेदन प्रस्तुत करने तक का है। दिनांक 19-6-2018 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया और पुनर्स्थापन का आवेदन दिनांक 17-12-2018 का है। आवेदक का अस्वस्थ होना दिनांक 18-6-2018 से 16-12-2018 तक दर्शाया गया है। मेडिकल सर्टिफिकेट की भाषा पर गौर करने से यह पाया जाता है कि संबंधित चिकित्सक द्वारा आवेदक तुलसीराम को प्रमाणपत्र जारी होने के दिनांक 16-12-2018 को परीक्षण कर पाया कि वे हेपेटाइटिस-बी से 6 माह से ग्रस्त हैं। साथ ही दिनांक 18-6-2018 से लेकर 16-12-2018 तक के 6 माह की अवधि में उनका स्वास्थ्य पूर्णतः ठीक होना दर्शाया है। प्रश्न यह है कि प्रमाणपत्र दिनांक 16-12-2018 को जारी हुआ</p>	

है तब चिकित्सक द्वारा यह कैसे अंकित कर दिया कि 6 माह पूर्व अर्थात् दिनांक 18-6-2018 से वह अस्वस्थ था और स्वस्थ होने के लिए यह अवधि आवश्यक होगी। प्रमाण पत्र की भाषा व स्पेलिंग की कई त्रुटियां हैं। मसलन हेपेटाइटिस की स्पेलिंग ही गलत है। ऐसी अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमाण पत्र किसी अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा बिना समुचित आधारों के जारी किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त मेडीकल सर्टिफिकेट के अतिरिक्त उपचार के दवाईयों के पर्चे सम्मिलित नहीं किये हैं जिससे बीमारी के इलाज की पुष्टि होती हो। चूंकि पुनर्स्थापन का आवेदन भी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है अतः अस्वीकार किया जाता है।

मेडिकल प्रमाण-पत्र की प्रति पृथक से हरदा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस निर्देश के साथ भेजी जाये कि वे प्रमाण-पत्र की जांच कर देखें कि क्या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा तथा किन परिस्थितियों में यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रतिलिपि कलेक्टर को भी Follow up हेतु भेजी जाये।

(जे०के० जैन)
सदस्य